# 582वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 29 जून 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 582वीं बैठक दिनांक 29/06/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

**1. <u>Case No 7505/2020 M/s Ram Janki Granite, Village - Didwara, DIst. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.20 ha. (19637 cum per annum) (Khasra No. 1593/1, 1594/1), Village - Didwara, Tehsil - Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur (MP) (In-Situ Enviro Care, Bhopal)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1593/1, 1594/1), Village - Didwara, Tehsil - Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur (MP) 1.20 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 459वीं दिनांक 23/09/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है। सेक की 580वीं बैठक दिनांक 23/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 29/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन–लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अजय मोहन उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र

के पूर्वी भाग में 05 पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस क्षेत्र को नॉन माईनिंग जोन (पूर्वी भाग से लगभग 160 मीटर तक) छोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है, अतः कोई भी पेड़ नहीं काटा जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र उत्तर–पूर्वी भाग से 230 मीटर दूरी पर तालाब है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गारलेंन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किया गया है तथा सेटल्ड वाटर का निस्तारण किया जायेगा । खदान के पश्चिमी भाग से लगा हुआ एक कच्चा रोड निकल रहा है इसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक अन्य खदान का पहुच मार्ग है तथा सुरक्षा की दृष्टि से उनके द्वारा 10 मीटर का सेट वैक प्रस्तावित किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान का पूर्वी क्षेत्र का भाग बहुत सकरा है जिसकी चौडाई लगभग 20 मीटर है तथा 15 मीटर का वैरियर जोन छोडने के बाद सिर्फ 05 मीटर की जगह ही बचती है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् की इस जगह को नॉन माईनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है । समिति ने खनन् योजना के अवलोकन से पाया कि उपलब्ध खनिज की मात्रा अनुसार इस खदान् की वर्किंग लाईफ मात्र 05 वर्ष है ।

समिति ने पाया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान जनसामान्य द्वारा ब्लास्टिंग व फ्लाई रॉक से परेशानी, धूल की समस्या, खनन् हेतु पानी की आपूर्ति, खदान के चारो ओर फेसिंग तथा वृक्षारोपण संबंधी आपत्तियां/कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग (माफल) की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार धूल नियंत्रण हेतु सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु पानी की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत दिदवारा की सहमति उनके पत्र क्रमांक 10/22 दिनांक 10/3/22 के माध्यम से प्राप्त की गई है। समिति ने पाया कि इस खदान की जन–सुनवाई के कार्यवाही विवरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों में ई.सी. की शर्तो का पालन नहीं हो रहा है । अतः समिति के अनुशंसा है कि सिया के द्वारा किसी स्वतंत्र शासकीय संस्था से यह परीक्षण कराया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं । इसी प्रकार संबंधित जिलाध्याक्ष / खनिज अधिकारी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त खदानों के ई.एम.पी. (जेसे पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण – बेरियर जोन तथा मिनरल इवेक्वेशन रोड के दोनो ओर, पक्का इवेक्वेशन रोड़, ओ.बी. मेनेजमेंट यादि) तथा सी.ई.आर. में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व सामाजिक विकास के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाये ताकि इस क्षेत्र में आने वाले समय में प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत ई.आई. ए. रिपोर्ट में टॉर के विशिष्ठ शर्तो/बिंदुओं का उचित एवं सारगर्भित उत्तर/पालन प्रतिवेदन नहीं दिया गया है जो दिया जाना चाहिए था । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ ई.आई.ए. रिपोर्ट में टॉर के विशिष्ठ शर्तो/बिंदुओं का उचित एवं सारगर्भित उत्तर/पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित फार्म–2 में जानकारी ।

- ✓ खदान के पश्चिमी भाग से लगा हुआ एक कच्चा रोड निकल रहा है अतः 10 मीटर के सेट वैक के साथ पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि इस खदान् से मात्र 05 वर्ष तक खनन् किया जायेगा।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. योजना ।

**2. <u>Case No 7341/2020 M/s S.B.Granites Ltd, 614, Apex Mall, Lal Kothi, Tank Road, Dist. Jaipur, Raj. – 302015 Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 2.50 ha. (500 cum per annum) (Khasra No. 28/1) at Village- Silpatpura, Tehsil- Chandla, District- Chhatarpur (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.</u>**

This is case of Granite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 28/1) at Village- Silpatpura, Tehsil- Chandla, District- Chhatarpur (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 449nd SEAC dated 24/07/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

सेक की 558वीं बैठक दिनांक 04/03/22 एवं 554वीं दिनांक 23/02/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

प्रकरण सिया की बैठक क्रमांक 728 दिनांक 27/5/22 में लिए गए निर्णय अनुसार रिलिस्ट कर सेक को एप्राइज हेतु भेजा गया है ।

सेक की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 579वीं दिनांक 17/06/22 एवं 582वीं दिनांक 29/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियेाजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

**3. <u>Case No 9249/2022 Shri Vaibhav Gandhi, Owner, 21, Kila Jobat Marg, Dist. Alirajpur, MP - 457990, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.60 ha. (47025 Cum per annum) (Khasra No. 78, 81, 279, 280, 281, 286, 287, 288), Village - Kolyabayda, Tehsil - Jobat, Dist. Alirajpur (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 78, 81, 279, 280, 281, 286, 287, 288), Village - Kolyabayda, Tehsil - Jobat, Dist. Alirajpur (MP) 3.60 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 669 दिनांक 08/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 उत्खनिपट्टा खदानें क्रमशः प्रमिला पति विजय गांधी, 0.94 हे. एवं श्रीमती संगीता पति विजय गांधी, रकबा 1.500 हे. क्षेत्र स्वीकृत होकर जिसकी अवधि पूर्ण (समाप्त) हो गई है । अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान का उत्तरी–पश्चिमी भाग खुदा हुआ है जिसमे संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान उनको मई, 2022 में स्वीकृत हुई है तथा पूर्व में किसी अन्य आवेदक को इस खदान का कुछ खनन् हेतु आवंटित हुआ था जिनके द्वारा इस क्षेत्र में खनन् कार्य किया गया है । मेरे खदान पर जो पिट दिख रहा है उसका उल्लेख अनुमोदित खनन् योजना के सरफेस मेप में किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्र (क्रमांक 669 दिनांक 08/06/22) के इसी आवेदित क्षेत्र में 02 अन्य उत्खनिपट्टा खदानें क्रमशः प्रमिला पति विजय गांधी, 0.94 हे. एवं श्रीमती संगीता पति विजय गांधी, रकबा 1.500 हे. क्षेत्र स्वीकृत हुई थी जिनकी अवधि पूर्ण (समाप्त) हो गई है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में 390 मीटर पर आबादी है, उत्तर दिशा में 270

मीटर पर पक्का रोड़ है तथा उत्तर दिशा में आवंटित खनन् क्षेत्र के पास में 02 क्रेशर स्थापित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पूर्वी क्षेत्र में कुछ पेड़ (03–04) लगे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ा गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 47025 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 06.47 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख :–

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|
| ग्राम कोल्याबरड़ा के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी के परामर्श एवं जरुरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण प्रदान किये जावेंगे । | 70,000/- |
| **योग** | **70,000/-** |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन के अंतर्गत | चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, बरगद, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 2000 पौधे |
| 2 | परिवहन मार्ग ( पेड़ों की न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर) | पीपल, करंज, बरगद , चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 250 पौधे |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | ग्राम कोल्याबरड़ा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में | कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल ,आवला करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 50 पौधे |
| 4. | ग्राम सुदी बड़ी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में | पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 250 पौधे |
| 5. | ग्राम कोल्याबरडा के शासकीय हाई स्कूल परिसर में | नीम, चिरोल, पुत्रंजीवा, पीपल, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 250 पौधे |
| 6. | ग्राम बीड़ा बाड़ी में स्थित शासकीय खेल मैदान में परिसर में | पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 400 पौधे |
| 7. | ग्रामीणों में पौधो का वितरण | आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 1200 पौधे |
| | | **कुल वृक्षारोपण** | **4400** |

**4. <u>Case No 9250/2022 Shri Deep Narayan Singh, Lease Owner, R/o- Village-Akauna, Post- Aber, Dist. Satna, MP - 485226, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.613 ha. (14950 Cum per annum) (Khasra No. 395/1 (P)), Village - Patarhai, Tehsil - Rampur-Baghelan, Dist. Satna (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 395/1 (P)), Village - Patarhai, Tehsil - Rampur-Baghelan, Dist. Satna (MP) 2.613 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1124 दिनांक 02/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 सदृश खजिन का उत्खनिपट्टा रकबा 01.672 हे. एवं 02 मुख्य खनिज उत्खनिपट्टा कुल रकबा 716.294 हे. स्वीकृत है, इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर सदृश खदानों का कुल रकबा 04.375 होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन केएमएल इमेज अपलोड नहीं की गई है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण गूगल इमेज ऑनलाईन सही

तरीके से अपलोड नहीं हो पाई है, इसी कारण ऑनलाईन नहीं खुल रही है, अतः माइन प्लॉन में उल्लेखित को–आर्डिनेट के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किये जाने का अनुरोध है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में आबादी है, अतः खनन् क्षेत्र में 90 मीटर का सेट–बैक छोड़ा जाना होगा तथा पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत किया जाना होगा । इसी प्रकार खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 180 मीटर पर पक्का रोड़, उत्तर दिशा में 90 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा दक्षिण दिखा में 60 मीटर पर प्राकृतिक नाला है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले के कारण गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये है तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा । प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि एकल प्रमाण–पत्र में उल्लेखित है कि खनन् क्षेत्र में 02 अवैध मकान बने है, अतिक्रमण के रूप में । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये दोनों ही मकान अवैध कब्जे के है जो आसपास के किसानों द्वारा कृषि कार्य में उपयोग आने वाले सामान को रखने हेतु बनाये गये हैं तथा जब वे खनन् कार्य प्रारंभ करेंगे तब उन्हें वहॉ प्रशासन द्वारा विस्थापित किया जायेगा । समिति ने उपरोक्त के संदर्भ में यह अनुशंसा की कि यदि इन दोनों मकानों में कोई निवासरत् है तो परियोजना प्रस्तावक खनन् कार्य इन दोनों मकानों के विस्थापन के पश्चात् ही प्रारंभ करेगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में आबादी है, अतः खनन् क्षेत्र में 90 मीटर का सेट–बैक दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 14,950 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.96 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 05.12 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख :–

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|
| ग्राम पतरहाई के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व 1वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा। | 70,000 |
| **योग** | 70,000 |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3150 वृक्षों का वृक्षारोपण :

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन में वृक्षारोपण | सिस्सू, नीम, खमैर, चिरौल, पीपल, सेमल, अशोक, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 1500 |
| 2 | परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) | नीम, पीपल, चिरौल, करंज,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, | 250 |
| 3 | पतरहाई ग्रामवासियों में वितरण हेतु | बेल, इमली, आंवला, आम, सीताफल, मुनगा इत्यादि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 1380 |
| 4. | शासकीय विद्यालय पटराहाई में | कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार इत्यादि। | 20 |
| | | **कुल वृक्षारोपण** | **3150** |

**5. <u>Case No 9226/2022 Shri Suraj Singh Baghel Lease Owner, Village – Pateri , Tehsil – Bahri, District - Sidhi, MP - 486771 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.65 ha. (39002 Cum per annum) (Khasra No. 1050(P)), Village - Dadhiya, Tehsil - Bahri, Dist. Sidhi (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1050(P)), Village - Dadhiya, Tehsil - Bahri, Dist. Sidhi (MP) 2.65 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 580वीं बैठक दिनांक 23/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 29/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण

रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 41 दिनांक 23/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। एकल प्रमाण पत्र अनुसार 250 मीटर की परिधि के अंदर होने से वन समिति की बैठक दिनांक 29/12/21 के एजेण्डा बिंदु क्रमांक–10 विचारार्थ प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 32 मीटर दूरी छोड़कर एवं स्थल पर वन सीमा की ओर वृक्षारोपण करने तथा चेनलिंग फेंसिंग एवं ट्रेंचिंग कार्य कराये जाने के उपरांत उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही के छायाचित्र एवं मौका पंचनामा संबंधित कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान पहाड़ के ऊपर स्वीकृत है जिसके पूर्व दिशा में 25 मीटर पर कच्चा रोड़ है, उत्तर–पश्चिम दिशा में 50 मीटर पर आबादी तथा सम्पूर्ण लीज क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं । आबादी को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन् योजना में ब्लास्टिग प्रस्तावित है किंतु उनके द्वारा आबादी को ध्यान में रखते हुए खनन् रॉक ब्रेकर से किया जायेगा तथा आबादी से एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21/7/20 के अनुरूप 100 मीटर का नॉन माईनिंग जोन प्रस्तावित किया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है । चूकि सम्पूर्ण लीज क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं इस कारण समिति ने प्रकरण के साथ ऑन लाईन प्रस्तुत खसरा पी–2 फार्म का अवलोकन किया तथा पाया कि पी–2 फार्म में कैफियत ''म.प्र.शासन इमारती लकड़ी हेतु'' दर्ज है । समिति ने चर्चा के दौरान पाया कि चूँकि पी–2 फार्म में खसरे की कैफियत ''म.प्र.शासन इमारती लकड़ी हेतु'' दर्ज है अतः इसका लैंडयूज खनन् हेतु परिवर्तित करने बावत् इसका वैधानिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया जा कर निर्णय लिया जाना उचित होगा । अतः समिति की अनुशांसा है कि उपरोक्त संदर्भ में प्रकरण मार्गदर्शन हेतु सिया को प्रेषित किया जाये ।

**6. <u>Case No 9193/2022 Shri Jitendra Yadav, Owner, A-2, Mandakini Block, Kevihgar Line 1, Batalian, Dist. Indore, MP - 453111 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.20 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 178/228/1), Village – Alwasa Tehsil Mhow, Dist. Indore (MP)</u>**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 178/228/1), Village - Alwasa, Tehsil - Hatod, Dist. Indore (MP) 1.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला,

फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 122 दिनांक 10/01/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई (01 उत्खनन पट्टा स्वीकृत जो मा. न्यायालय के आदेश से शिथिल अवस्था में) खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर के अंदर एक उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है । समिति को उपरोक्त एकल प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव इस खदान पर भी लागू है या नहीं । अतः इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक से मा. उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के बारे में जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी उनके पास इस संदर्भ में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः जानकारी प्रदाय करने हेतु 10 दिन का समय दिया जाये । अतः समिति की अनुशंसा है कि मा. उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण की अद्यतन वस्तुस्थिति से 10 दिनों में अगवत कराया जाये, तत्पश्चात् प्रकरण विचार किया जावेगा ।

प्ररियोजना प्रस्तावक ने ऑन लाईन जबाब 05/6/22 को प्रस्तुत किया, जिसे सेक की 578वी बैठक दिनांक 16/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण आज दिनांक 29/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 05/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें पाया गया कि मान्नीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 के द्वारा बी.एस.एफ. की रेवती रेंज के समीप स्थित खदानों में निम्नानुसार खनन् हेतु रोक लगाई गई :–

"The area which is subject matter of the present writ petition as well as the other areas which are under the Green Belt/hillocks no mining activity shall be carried out by any person including the State Government".

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आदेश के साथ उन 20 खदानों की सूची भी ऑन लाईन प्रस्तुत की है जो उपरोक्त आदेश के तहत् बंद की गई है जिसमें से 04 खदाने उसी ग्राम अलवासा की है तथा जहां प्रश्नाधीन खदान भी है तथा कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा पत्र क्रमांक 122 दिनांक

10/01/22 के माध्यम से जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर के अंदर एक उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है ।

अतः उपरोक्त संदर्भ में समिति की अनुशंसा हेतु कि खनिज अधिकारी से 15 दिवस में यह जानकारी प्राप्त की जाये कि मान्नीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 जारी दिशा निर्देशो के बावजूद भी प्रश्नाधीन खदान को क्यो स्वीकृती प्रदान की गई तथा क्या मान्नीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा जारी आदेश दिनांक 17/01/2020 इस खदान पर लागू नही होता । इस संदर्भ में खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् इस प्रकरण पर निर्णय लिया जावे ।

**7. <u>Case No 9162/2022 M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP, SHri Shubham Jain, Partner, Main Road, Goberwahi, Dist. Balaghat, MP - 481445 Prior Environment Clearance for Green Field Project of Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity - 0.5 MTPA) at Village Selwa, TehsiI - Katangi, District - Balaghat, MP</u>**

This is case of Prior Environment Clearance for Green Field Project of Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity - 0.5 MTPA) at Village Selwa, TehsiI - Katangi, District - Balaghat, MP.

The TOR was issueed by MoEF&CC vide letter dated 23/09/2020. PP has submitted the EIA report on line which was forwarded through SEIAA and the same was scheduled in the agenda.

Earlier the case was discussd in the 572nd SEAC meeting dated 19/05/22 wherein it is mentioned that:

The EIA was presented by the PP Shri Venketash M. and Env. Consultant Dr. Dheeraj K. Singh & Ms. Mudita Tomar Singh from M/s. Grass Roots Research & Creation India (P) Ltd., Noida (U.P.), wherein PP submitted that they have obtained TOR from MoEF&CC vide no. J-11011/177/2020-IA.II (I), dated 23.09.2020. PP further submitted following details of the project:

| S.NO. | PARTICULARS | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | Date of Grant of ToR | 23.09.2020 |
| 2. | Baseline Study Period | Winter season 1st Dec. 2019 to 28th Feb. 2020 |
| 3. | Date of Public Hearing | 19.03.2021 |
| 4. | Project Cost | INR 5.0 Crores |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | EMP Cost (Capital and Recurring) | Capital Cost – INR 148 Lakhs<br>Recurring Cost – INR 56.5 Lakhs/Annum |
| 6. | Manpower Details | During Construction – 50-100 Persons<br>During Operation– 38 Persons |
| 7. | Details If Project Falls under the Purview of<br>A) FCA,1980, B) WLPA,1972, C) CRZ, 2011 | Not Applicable |
| 8. | CPA/ SPA/ ESA/ ESZ, If Any | None in 10 km distance around the project site |
| 9. | Interlinked Project, If Any, With Status | Not Interlinked |

**Proposed Unit Configuration with Capacity in MTPA:**

- M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP proposed to install 0.5 MTPA capacity manganese ore beneficiation plant.
- Total plant capacity : 0.5 MTPA
- Final Product: Beneficiated Ore. 0.375 MTPA
- Project Category 'B', at Serial No. 2 (b) Mineral Beneficiation as per latest notification dated 20.04.2022.
- Source of the raw material will be Private manganese mines, Manganese Ore India Private Limited of Balaghat District which are located within 20-30 km radius of the project site and will be transported through road.

During presentation, following observations are made by the committee and PP was asked to submit justified reply with necessary amendment in EIA report:

1. In form-II at Sl no. 14.6, See ground water table details. How it is possible that post monsoon table is 05 to 10 meters while pre monsoon table is 04 to 08 meters.
2. In form-II at Sl no. 16.2, Capacity of STP is provided as 03.00 KL but no wherein in EIA report, STP's drawing & designs are discussed.
3. In form-II at Sl no. 17.1, Tailings are proposed to be used for backfillings. No justification for this proposed method of disposal is provided such as TCLP analysis.
4. In form-II at Sl no. 17.2, MSW is proposed to be disposed through authorized recyclers. Please provide the list of authorized recyclers for this purpose.

5. In form-II at Sl no. 25, No tree cutting is proposed while as per google image some trees are in existance within the lease area and as per the proposed layout in EIA report, some industrial facilities are mentioned at these locations. Please justify your statement.
6. Refer figure 2.6 of EIA (p/30) Justify the statement that manure will be used for filling in low lying area.
7. Refer figure 2.6 of EIA (p/30) It is proposed that domestic waste water will be tyreated through soak pit anf septic tank while in form-II at Sl no. 16.2, STP is proposed which is a mismatch in the information provided, please justify.
8. Refer point no. 2.4.5 of EIA (p/31) wherein it is proposed that "Sludge after digestion is used as manure", please justify what kind of digestion will be provided.
9. Refer point no. 2.4.5 of EIA (p/32) volume of MSW is mentioned as 100 kg/month (i.e. 01.2 TPA approx) while in form-II 17.2 the mentioned volume of MSW is 36.5 TPA, please justify the appropriate quantity of MSW.
10. See Table 6-3 of EIA (p/152): Cost of Environmental Monitoring Program- GW monitoring points shall be enhanced to 04 (one in each in all corners of lechate collection tanls/settling tanks locations corresponding to aquifer movement)
11. See Table 10.2 of EIA (p/183): Investment on Environmental Protection Measures- Add cost of industrial vaccume cleaners, all internal roads paved etc as per the TOR prescribed by the MoEF&CC.
12. See Table 10.2 of EIA (p/183): Add cost of water treatment and recycling system such as lechate ponds, their lining etc.
13. Justified compliance of TOR point no. (ii) Issued by MoEF&CC for water drawal from Chandan River.
14. Justified compliance of TOR point no. (v) How 100% solid waste will be resued.
15. Following details are not provided in EIA report as per Standard TOR prescribed by MoEF&CC:
    i. Details of settling tanks are missing (if proposed)
    ii. Material balance/ Mass balance.
    iii. Management and disposal of tailings & closure plan of tailing ponds. (Their volume, details of HDPL/LDPL etc are missing.
    iv. Proposal for Silos for storage of raw material and tailings are missing.

16. Commitment of PP that stock pile which is to be used in feeding to hopper for benefication shall always have 15-20% moisture to avoid fugitive emission of dust and stored stock pile must have minimum 15% moisture.
17. PP comprehensive proposal for "Zero Liquid Discharge".
18. Revised EMP and CER as suggested by committee.
19. Copy of lechate analysis report.
20. Commitment of PP that all internal roads will be made pucca/paved.
21. Under Generic Terms of Reference (TOR) point no. 3-V- Other chemicals and materials required with quantities and storage capacities. Here, PP mentioned that there are no any chemicals used in process. However, some chemicals required to treat the wastewater. Which chemical? please justify.
22. In the Form -2 point no. 8.2 under heading -Product- Tailing (Waste) - 0.12 Millon Tons per day mentioned please justify how this huge quantity shall be generated per day.
23. In the Form -2 point no. 13.1 under heading Raw Material / Fuel Profile as DG set of 25kVA is proposed but under this fuel details is missing.
24. In the Form -2 point no. 30.0 under heading Details of Presence of Water Bodies in Buffer Area- PP mentioned only Chandan River but at a distance of 180 m in the south side Balwa nalla exists which is not discussed please justify.
25. In the EIA report under page no. 47 para 3.6.4 –D, mentioned that coal mine activity around the project side. Please justify where such coal mine observed in the 10 KM of study area.
26. Under TOR compliance point no. 7-VII - Details of hazardous waste generation, PP has not mentoned details of waste oil generated through DG set. Please justify.
27. Under TOR compliance point no.7- V Details of stack emission – height mentione is 30 m while in Form -2 (18.2) is mentione as 05 m.

PP vide their letter dated 18/06/2022 uploaded online query reply raised in the 572nd SEAC meeting dated 19-05-22 on "Parivesh Portal" and submitted revised Form-II, revised EIA report and query reply and thus the case was scheduled for presentation in this meeting.

The case was presented by the PP and their consultant, wherein PP submitted following details:-

- The composition of tailing will be mainly Quartz which is a non-hazardous waste. Coarse and Sandy silica rich tails are likely to be used as aggregates the tails are filtered material.

- The slimy tails are sent back to the abandoned mines for consolidation and cementing material of mine wastes A schematic diagram of filtered Mn plant fine tails and waste rock in abandoned Mn mine with vegetation is shown in the report. Hence, TCLP analysis not required.
- MSW will be disposed through Gram Panchayat. Copy of NOC has attached as Annexure.
- There are no trees present at project site. Some bushes exist which will be cleared before start of construction work.
- Regarding justify the statement that manure will be used for filling in low lying area.
- MSW will be disposed through Gram Panchayat. Copy of NOC has attached as Annexure.
- There are no trees present at project site. Some bushes exist which will be cleared before start of construction work.
- Regarding justification the statement that manure will be used for filling in low lying area. The correction has been made. Updated EIA/EMP report is attached.
- Reject generated will be used for filling in low lying area. Revised Water Balance is given.
- The domestic waste water will be disposed through septic tank and soak pit.
- EMP Capital cost has been updated from INR 148 Lakh to INR 165 Lakhs and Recurring cost revised from INR 56.5 Lakh to INR 57.0 Lakh.
- Chips (Quartz) forms of tailing waste will be reused in construction of paved road and slime form of tailing waste will be used in back filling/reclamation of Manganese Mine at Balaghat being operated by M/s Metal & Minerals. MoU has been signed with M/s Metal & Minerals regarding the same.
- Settling tanks are not proposed as all the outgoing products are filtered and reclaimed.
- Filtrate water is reused in the process and it is a Zero waste physical separation process with no addition of chemicals producing a host of Mn rich, Silica rich main co and by products**.**
- There is no proposal for Silos. Separate yards are proposed for storage of raw material, main, co products and less valuable products [tailings] with adequate facilities.
- We assuring that stock pile which is to be used in feeding to hopper for beneficiation shall always have 15-20% moisture to avoid fugitive emission of dust

and stored stock pile must have minimum 15% moisture. We have submitted undertaking regarding the same.

- No effluent generation from the process. Water from filter press will be collected and recycled back into the system. Sewage will be disposed through septic tank and soak pit.
- The composition of tailing will be filtered solids containing mainly Quartz which is non- hazardous waste (assaying 86.42% $SiO_2$ and 7.03% Mn).
- We have committed that all internal road will be Pucca/Paved. An undertaking regarding the has been already given. Also we will construct 500m road in Selwa village and maintenance work for 1 year. A budget of INR 7.0 Lakh has been kept for Road Development and maintenance work under CER.
- Chemicals to be stored at site include the chemicals required for treatment of the wastewater including non-toxic, eco-friendly flocculants (100 Tons/Month) which will be stored in covered shed.
- Very little quantity, approx. 0.005 KL/annum of waste oil will be generated will be generated from DG set which will be stored in covered HDPE drums in a designated area and will be given to authorized vendors.
- DG Stack height will be 30m.

After presentation Committee asked PP to submit following clarification / information's:-

- PP should submit Distance of MSW Disposal site from the Project area for which NOC granted by Gram Panchayat Selwa.
- PP commitment that no tree cutting is proposed project area.
- PP Should submit revised water consumption details.

PP vide their letter dated 29/06/2022 submitted the query reply which was placed before the committee and the same found satisfactory. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for 0.5 Million Ton per Annum Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity - 0.5 MTPA) at Village Selwa, TehsiI - Katangi, District - Balaghat, MP. Cat. 2(b) Mineral Beneficiation Projects subject to the following special conditions:

**(A) Statutory compliance:**

1. Benefication of 0.5 MTPA will result in the beneficiated Mn Ore 0.375 MTPA and Tailing (Waste) 0.125 MTPA.

2. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
3. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time & permission of competent authority if ant tree falling is to be carried out.
4. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

**(B) Air quality monitoring and preservation**

1. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
2. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS.
3. The DG set of 25 kVA shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
4. DG set of 25 kVA exhaust will be discharged at height stipulated by CPCB.
5. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161h November, 2009 shall be complied with.

**(C) Water quality monitoring and preservation**

1. About 84.4% of the total process water is reclaimed and reused. Reclaimed Process waste water will be immediately collected from thickeners and filers in reclaimed water tanks and circulated back in the washing circuit. Zero effluent discharge will be practiced and No chemicals are used in the process.
2. No effluent generation from the process. Water from filter press will be collected and recycled back into the system. Sewage will be disposed through septic tank and soak pit.

3. CGWB has given NOC for fresh Ground Water Abstraction for 335.00 $m^3$/day (110550.00 $m^3$/year) which is valid upto 30/10/2023. If additional GW required further, PP can apply Central Ground Water Board North Central Region. PP shall comply Mandatory conditions & General conditions imposed by CGWB.
4. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent (if applicable), the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
5. As already committed by the project proponent Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises, for which PP shall provide Thickener, Filter Press and recycling system for making system zero discharge
6. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
7. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
8. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
9. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
10. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

**(D) Noise monitoring and prevention**

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG set of 25 kVA for controlling the noise pollution.

2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

**(E) Energy Conservation measures**

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.

**(F) Waste management**

1. Rejects – 0.125 MTPA silica rich rejects generated & will be used as aggregates co-product and filtered slimes shall be reused for making of pavered blocks after getting scientific studies conducted through an agency of national reput.
2. For as backfilling of rejects in abandoned Mn mines, comprehensive analysis of rejects for its hazardous constituents such as heavy metals and TCLP shall be carrioedout and after the approval of MP Pollution Control Board.
3. Municipal Waste - 100 kg per month municipal waste will be generated, which will be disposed through Gram Panchayat and after composting may be used as manure that will be used along with top soil over the mine tails waste dumps to grow vegetation.
4. Hazardous Waste Generation, Storage & Disposal - Very little quantity, approx. 0.005 KL / annum of waste oil will be generated will be generated from DG set which will be stored in covered HDPE drums in a designated area and will be given to authorized vendors.
5. PP shall explore the possibility of “waste wealth concept” by using quartz/ reject as alternate substitute raw material in the paver blocks manufacturing or other fruitful purposes after getting scientific test from approved laboratory.
6. The stock pile which is used in feeding to hopper for beneficiation shall always have 15-20% moisture to avoid fugitive emission of dust and stored stock pile must have minimum 15% moisture.
7. The solid tailings shall used by Cement Industries, for bricks manufacturing nearby bricks plant, or paver blocks after conducting scientific study through an institute of national reputed within a year and their findings shall be submitted with six monthly compliance reports.

8. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
9. Hazardous wastes such as used oil, discarded drums, used carbon (if any) etc shall be directly sent to nearby approved vendors.
10. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
11. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
12. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
13. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
14. All the storage area of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks.
15. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.

**(G) Green Belt**

1. A greenbelt of 1.007 ha (33.0% of Total Plot Area) will be developed in the plant premises. Greenbelt will be developed around the plant, along the transportation road and nearby Village within initial 2 Yrs. total 4500 No's no of trees shall be planted in the next two years as follows:

| Schedule | Species | Number | Place |
|---|---|---|---|
| 1st and 2nd Year | Biza, Kusum, Haldu, Kachnar, mahua, Dahiman, Achar, Guava, Kathal Salyakarni and local species etc. | Biza -250, Kusum,-200 Haldu - 100, Kachnar- 150, Mahua- 200, Guava-200, Kathal-150,Dahiman-100,Salyakarni- 150 Total =1500 | Along the project boundary |
| 1st and 2nd Year | Biza, Kusum, Haldu, Kachnar,mahua, Guava, Kathal | Biza -150, Kusum,-200 Haldu - 100, Kachnar- 150, Mahua-200, Guava-200,Kathal-150, Total = 1150 | Along the transport Road |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1st and 2nd Year | Biza, Kusum, Haldu, Kachnar, mahua, Dahiman, Achar, Guava, Kathal Salyakarni and local species etc. | 1850 Nos. | For distribution at Village |

2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 01 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
3. PP shall also develop green belt over community places in consultation with gram panchayat .

**(H) Safety, Public hearing and Human health issues**

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

**(I) EMP& CER**

1. The proposed EMP cost is Rs. 165.00 Lakhs as capital and 57.0 Lakhs /year as recurring cost.

2. PP shall propose physical targets based on public hearing under Corporate Environment Responsibility (CER).

| S. No. | Issue Raised during PH | Physical activity and action plan | Budget | 2022-2023 | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providing employment to local people | Willing and employable youths will be identified in consultation with gram panchayat of Selwa (30 Nos). They will be trained in Katangi ITI for trades namely electrician, fitters, welders, painters, and civil construction work, etc. Fees will be paid by us. Scholarship of Rs.1000/-per month will be given to the trainees for the entire duration. After successful completion of training, the youths will be offered employment in company. | **16.2 Lakhs**<br><br>Stipend – 4.20 Lakh (800/- stipend to 50 persons for 1 year)<br><br>ITI Fee – 12 Lakhs (26000/- yearly fee for 50 persons) | Training of 25 persons will be completed in 1st year | Training of 25 persons will be completed in 2nd year |
| 2 | Infrastructure development of local School and development of green belt in village Selwa | PP will make separate toilets for boys and girls (in 2 local schools around the project, in Village-Selwa, Bhajiyapar and Village-Gopalpur (1 schools), kitchen in 3 local schools supplying mid- day meals, providing furniture, computers and colour printers | **10 Lakhs**<br>6 Toilets–1 Lakh, 3 Kitchen – 1.5 Lakh, 400 -Tables &Chairs– 4.0 Lakh, 12 Computer–3.0 Lakh, 3 Colour printer-1.5 Lakh.<br><br>**5 Lakhs**<br><br>Development of green belt in Selwa village (2000 trees) | We will complete work in Village-Selwa<br><br>& Bhajiyapar schools (2 schools) 1000 trees will be planted | We will complete work in school Village-Gopalpur (1 School) 1000 trees will be planted |
| 3 | Drinking Water | Company will make arrangement for | **7 Lakhs** | We will complete | We will complete |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Supply in nearby areas | drinking water facility with pump, piping and RO system in 3 surrounding villages. (Village-Selwa and Bhajiyapar ) | Up gradation of drinking facility in nearby villages. | drinking water supply in Selwa village. | drinking water supplyin Bhajiyapar village. |
| 4 | Road Development and maintenanc e work in Selwa Village | Company will construct the 500 mtr road in Selwa village and maintenance work for 1 year. | **7 Lakhs**<br><br>Road development work in Selwa village in consultation with local authority. | Work will complete in Selwa village. | -- |
| 5 | Concern about health of local people | Donate medical equipment like Beds, Stretcher, Portable Oxygen Cylinder (330 Litre), Oxygen Concentrator (0.5 to 5 Ltr ), Air Purifier (Honeywell Air Purifier with Capacity of 300m$^3$/hr), AC (Window AC of 1.5 Ton ), in Health center of Chitrangi | **10 Lakhs**<br><br>Ten Bed-1.0 Lakhs, Ten $O_2$ Cylinder-1.5 Lakh, Four- Oxygen Concentrator – 4.0 Lakh, Four Air Purifier– 1.5 Lakh, Four AC- 2.0 Lakh | We will Donate to Health center at Katangi in consultation with area CMO officer. | - |
| **Total** | | | **55.20 Lakh** | | |

3. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
4. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
5. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate/company bank account.

6. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
7. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

**J. Miscellaneous**

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In case of deviations or alterations in the project proposal from those submitted to this Ministry for clearance, a fresh reference shall be made to the Ministry to assess the adequacy of conditions imposed and to add additional environmental protection measures required, if any
6. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**8. <u>Case No 9200/2022 Shri Shyam Singh Chouhan S/o Shri Tej Singh Chouhan, Paavti, Tehsil - Garoth, Dist. Mandsaur, MP - 458880 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 2625), Village - Paavti, Tehsil - Garoth, Dist. Mandsaur (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2625), Village - Paavti, Tehsil - Garoth, Dist. Mandsaur (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 723 दिनांक 05/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रशनाधीन खदान को मिलाकर कुल रकव 4.950 हे. होता है, अतः यह प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 315 मीटर तथा उत्तर में 500 मीटर पर मौसमी नाला है। इसी प्रकार खदान के दक्षिण–पूर्व में 500 मीटर पर, उत्तर में 770 मीटर तथा उत्तर–पश्चिम में 880 मीटर पर तालाब है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलीय निकाय के कारण गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये है तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा । लीज में कुछ पेड़ 03–04 है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से कोई पेड़ काटे नहीं जायेंगे । उत्तर दिशा से आकर पूर्व दिशा में एक प्राकृतिक नाला आ रहा है, जो दक्षिण दिशा में ही एक प्राकृतिक जल निकाय में मिल रहा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह क्षेत्र (0.30 हे.) नॉन माईनिंग एरिया के रूप में छोड़ा जायेगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ नॉन माईनिंग एरिया दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- ✓ प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ट्री–इंवेंट्री प्रस्तुत की जाये।

प्ररियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन दिनांक 24/6/22 को प्रस्तुत कर दी गई है ।

प्रकरण आज दिनांक 29/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 10000 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.00 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.95 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख :–

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|
| स्थानीय अनाथ एवं निशक्तजन संसथान मंदसौर में सहयोग राशि। | 50,000 |
| गरोठ प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 1ECG मशीन रिपोर्ट के साथ | 50,000 |
| **योग** | **1,00,000** |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

| क्रं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन में वृक्षारोपण | नीम,सिस्सू, करंज,चिरोल, सीताफल,सफ़ेद कैस्टर एवं अन्य प्रजातियाँ | 800 |
| 2 | परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) | नीम,करंज,चिरोल,जंगल जलेबी। | 300 |
| 3 | शासकीय विद्यालय परिसर में | मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम | 100 |
| | | कुल | 1200 |

## 9. Case No 9206/2022 Shri Amol Singh Ahirwar Prop. Village - Chanari, Post - Atta, Tehsil - Malthone, Dist. Sagar, MP - 470441, Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (1500 Cum per annum) (Khasra No. 162/3, 162/4), Village - Chanari, Tehsil - Malthone, Dist. Sagar (MP)

This is case of Flag Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 162/3, 162/4), Village - Chanari, Tehsil -

Malthone, Dist. Sagar (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 754 दिनांक 22/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर 05.00 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

वन मण्डलाधिकारी के पत्र अनुसार 135 मीटर की दूरी पर वन सीमा है, अतः लीज हेतु आपत्ति ली गई थी । तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04/02/22 का कार्यवाही विवरण के प्रकरण क्रमांक–2 ''सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदक आवेदित क्षेत्र ग्राम चनारी तहसील मालथौन जिला सागर के शासकीय भूमि खसरा नं0 162/3, 162/4, में रकबा 1.00 हे. क्षेत्र पर उत्खनन् पट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है । आवेदक वन सीमा की ओर, स्वीकृत क्षेत्र पर वन मण्डाधिकारी के निर्देशन में तार फेंसिंग करेंगा । उत्खनन् पट्टाधाारी वन भूमि के अंदर ओव्हर बर्डन नहीं डालेगा, स्वीकृत लीज में ही ओव्हर बर्डन डालेगा एवं वन भूमि से आवागमन नहीं करेगा । आवेदक स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं वन विभाग के अमले की उपस्थिति में सीमांकन कराकर सीमेंटेड कंक्रीट के पक्के मुनारे बनायेगा एवं खदान स्वीकृति से संबंधित खदान विवरणी बोर्ड स्थापित करेगा । स्वीकृत क्षेत्र में वन सीमा की ओर सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगवायेगा एवं कम से कम 15 दिन की रिकार्डिंग रखेगा । अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कार्य किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में 180 मीटर पर रोड़ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फ्लैग स्टोन का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित क्षेत्र के उत्तरी भाग में पुरानी गूगल इमेज अनुसार मार्च, 2020 से खनन् कार्य किया गया है । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मेरी खदान से लगी हुई खदान मालिक द्वारा गलती से मेरे खदान क्षेत्र में खुदाई कर ली गई तथा हमने इसे सरफेस में भी दिखाया गया है। श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम चनारी तहसील मालथौन जिला सागर द्वारा समिति को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के पत्र दिनांक 07/3/19 द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर में अन्य 04 खदानों की जानकारी देते हुए प्रकरण को बी–1 में विचार किये जाने का अनुरोध किया गया जबकि कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 754 दिनांक 22/04/22 अनुसार प्रस्तावित

खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है । अतः इस संबंध में खनिज अधिकारी, जिला सागर से सेक द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सीईआर योजना ।

प्ररियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन दिनांक 24/6/22 को प्रस्तुत कर दी गई है ।

प्रकरण आज दिनांक 29/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

समिति ने पाया कि श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम चनारी तहसील मालथौन जिला सागर से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के पत्र दिनांक 07/3/19 द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर में अन्य 04 खदानों की जानकारी देते हुए प्रकरण को बी–1 में विचार किये जाने का अनुरोध किया गया जबकि कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 754 दिनांक 22/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित उल्लेखित था । अतः समिति ने यह निर्णय लिया था कि इस संबंध में खनिज अधिकारी, जिला सागर से सेक द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए । समिति ने पाया कि प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के पत्र क्रमांक 1021 दिनांक 22/06/22 द्वारा जारी पत्र अनुसार ग्राम चनारी, तहसील मालथौन जिला सागर के खसरा नं. 162/3, 162/4 के रकबा 1.00 हे. क्षेत्र के आसपास 500 मीटर की परिधि में 03 उत्खनन् पट्टे स्वीकृत / संचालित है । समिति ने पाया कि प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, जिला सागर द्वारा पुनः 500 मीटर की परिधि में पूर्वानुसार 03 ही उत्खनन् पट्टे स्वीकृत / संचालित होने की जानकारी दी गई है । अतः प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, जिला सागर से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर चारों खदानों का कुल क्षेत्रफल 05.00 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। समिति ने प्परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन – 1500 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.77 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 03.06 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख :–

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|

| | |
|---|---|
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम चनारी में 05 व्हीलचेयर और 03 स्ट्रेचर | 60,000 |
| **योग** | 60,000 |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200. वृक्षों का वृक्षारोपण :

| **क्रं.** | **प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान** | **पौधों की प्रजातियॉ** | **मात्रा (संख्या में)** |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन में वृक्षारोपण | नीम, पीपल, शीशम, बरगद, आम, महुआ, इमली, चिरोल, बबूल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 800 |
| 2 | परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) | नीम, करंज, आम, शीशम, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 100 |
| 3 | ग्राम के ग्रामीणों में वितरण | ऑवल, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नीबू, हर्रा, बहेरा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया। | 300 |
| | | **कुल** | **1200** |

**10. <u>Case No 9220/2022 M/s Devi Construction, Prop., Shri Jitendra Kumar Pateria, Village - Berkheri, Post - Sahawan, Tehsil - Banda, Dist. Sagar, MP - 470337, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 564), Village - Berkheri, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 564), Village - Berkheri, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 966 दिनांक 25/05/22

अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 170 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर पक्की रोड़ है । इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर स्केटर्ड आवास हैं । आवंटित क्षेत्र प्राकृतिक जल धारा से निर्मित गुली पर स्थित है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ नॉन माईनिंग क्षेत्र (लीज के दक्षिणी–पूर्वी भाग) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी./वृक्षारोपण/सीईआर योजना ।

प्ररियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन दिनांक 24/6/22 को प्रस्तुत कर दी गई है ।

प्रकरण आज दिनांक 29/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । समिति के संज्ञान में लाया गया कि सिया के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 28/06/22 के माध्यम से प्रकरण क्रमांक 9920/2022 ग्राम बनखेड़ी तहसील बंडा जिला सागर, परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुमार पटेरिया के नाम से स्वीकृत खदान के संबंध में एक शिकायत उनको प्राप्त हुई है, जो उनके द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से निराकरण हेतु सेक को प्रेषित की गई है । प्राप्त शिकायत का समिति ने अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी राजा सिंह, ग्राम बनखेड़ी तहसील बंडा जिला सागर ने अपने पत्र क्रमांक निल दिनांक निल के द्वारा शिकायत की है कि –

*''सिया केस केस संख्या 9220/22 से पर्यावरण की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है जो कि स्वीकृति योग्य नहीं है 150 मीटर के अंदर आदिवासी रहवासी क्षेत्र स्थित है जिससे लोगों के घरों पर खदान से पत्थर एवं धूल आएगी जिसका लोगों की जीवनी पर बुरा असर होगा कृपया खदान की अनुमति किसी अन्य क्षेत्र में दी जाये उक्त जगह पर नहीं दी जाये ।*

समिति ने उपरोक्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में यह पाया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्र (क्रमांक 966 दिनांक 25/05/22) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई मानव बसाहट नहीं है किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्केटर्ड आवास स्थित हैं जो प्रश्नाधीन खदान से 200 मीटर से अधिक दूरी पर परिलक्षित हो रहे है। अतः समिति ने यह अनुशंसा की कि उपरोक्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार)

या प्रभारी, अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, सागर से यह प्रमाणिक जानकारी 15 दिनों के अंदर प्राप्त की जाये कि क्या प्रश्नाधीन खदान के 150 मीटर के अंदर कोई आदिवासी रहवासी क्षेत्र स्थित है जिससे लोगों के घरों पर खदान से पत्थर एवं धूल आएगी तथा उन लोगों की जीवनी पर बुरा असर होगा । उपरोक्तानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकरण में विचार किया जावेगा ।

**11. <u>Case No 6819/2020 M/s Atul Polychem, 2nd Floor, Amit Apartment, E-5, Ratlam Kothi, Dist. Indore, MP – 452001 Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin (From 2,700 to 11,000 MT/annum) at Khasra No. 58/1/K, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). Cat. - 5(f). Environmental Consultant:San Envirotech Pvt. Ltd.</u>**

This is the case for Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin at Khasra No. 58/1/k, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). The proposed project falls under item no 5(f).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 425$^{th}$ SEAC meeting dated 26/02/20 wherein ToR was recommended.

EC recommended in 458 SEAC meeting dated 22-09-20. EC granted in 642 SEIAA meeting dated 05-10-20. EC issued vide letter no. 4519-20/SEIAA/20 dated 27-10-20.

SEIAA has sent the on-line case file to SEAC on 23-06-22 for EC amendment. PP has applied for EC amendment in the prescribed form- 4.

The case was presented by the PP and their consultant wherein PP submitted that as per granted EC the total water requirement of plant after expansion will increase to 10.5 KLD and waste water generation will be 6.5 KLD (Domestic 2.0 KLD, condensate from process 3.5 KLD & cooling bleed off 1.0 KLD). PP further submitted that in their submitted EIA report they have proposed to send industrial effluent to CETP after primary treatment at site. However, as per granted EC, it has been instructed by H'ble SEIAA/SEAC M.P. to ensure "Zero Effluent Discharge" from the unit by recycling. To ensure ZLD, industry had explored the possibility of installation of "Zero Liquid Discharge" Plant & reuses the treated water within the premises. However, the capital & maintenance cost for ZLD Plant is expensive. Investment on ZLD plant will be expensive for the industry and the industry would not be able to manufacture the final product at a reasonable cost due to which economic viability will be lost as the cost of ETP for this unit will be approx. 70.00 lakhs.Thus we request the H'ble SEIAA/SEAC M.P. for amendment in EC to allow us to send industrial effluent after primary

treatment to CETP, Indore for further treatment & disposal. The case was scheduled for presentation and discussion in the 582nd SEAC meting dated 29/06/22.

After presentation PP was asked to submit following information for further consideration of the project:

1. Since during public hearing it was redommended by the district authorities that CETP at Sanwer Road, Indore is for the industries located in that area thus what are the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore? Please provide credible proof issued by the competent authorities to justify your proposal.
2. Detailed justification (component wise) of cost of proposed ETP for Rs. 75.00 lakhs.
3. How PP will ensure safe and spill proof transportation of waste water through tankers from plant site at Mangliya to CETP at Sanwer Road, Indore. How much distance will be travelled by road?

## 12. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – (रेत खनिज) – छतरपुर (संशोधित)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 815 दिनांक 21/06/22 के माध्यम से छतरपुर जिले की संशोधित (Revised) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, समिति के सदस्यों को दिनांक 20/06/22 को सॉफ्टकापी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में छतरपुर जिले की संशोधित रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग छतरपुर की ओर से श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी उपस्थित हुये उन्होने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट छतरपुर के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में जो सुझााव दिये गये थे, उनका समावेश रेत खनन के मामलें मे कर लिया गया है जिसके अनुसारः–

1. संबंधित अधिसूचना के तालिका में चाही गई जानकारी के अनुसार खनिज रेत हेतु लीजवार " माइनेबल मिनरल पोटेंशियल '' (घनमीटर में) (60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चोड़ाई के साथ) दिया गया है।
2. स्वीकृत 48 रेत खदानों के कोर्डीनेट्स (Co-ordinates) के अनुसार डिजिटाईज्ड मेप बनाने मे समय लगेगा तब तक जिले की 48 रेत खदानों के को–आर्डिनेट KML Files CD के माध्यम से जमा करायी गयी है।

समिति ने पाया कि प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अन्य गौण खनिज हेतु लीजवार वृक्षारोपण एंव निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व किये गये वृक्षारोपण की जानकारी निर्धारित प्रपत्र अनुसार नही दी गई है । इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे यदि कोई ESZ आता है तो उसका वर्णन,

विस्तार एंव सीमाएं एंव ESZ मे आ रहे गांवो का नाम का समायोजन नोटिफिकेशन के साथ होना अनिवार्य है। इसके साथ–साथ यदि जिले में खोदु–भरू खदान भी स्वीकृत है तो उनकी जानकारी भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल की जाना चाहिए । समिति की अनुशांसा हेतु कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप सभी बिंदुओ की जानकारीयों का समावेश होना चाहिए ।

खनिज विभाग छतरपुर की ओर से उपस्थित श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी ने बताया कि आज हुई चर्चा के अनुरूप वे सुधार कर रेत खनन् व अन्य माइनर मिनरलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अलग–अलग कर प्रस्तुत करेगे ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई कि वे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

## 13. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – बालाघाट (संशोधित).</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 845 दिनांक 24/06/22 के माध्यम से बालाघाट जिले की संशोधित (Rivesed)_जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बालाघाट, म.प्र. के पत्र क्रमांक 838 दिनांक 24/06/2022 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया /सेक कार्यालय मे ऑन लाईन जमा कराई गई। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, समिति के सदस्यों को दिनांक 27/06/22 को सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितिकी 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में बालाघाट जिले की संशोधित रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग बालाघाट की ओर से श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी उपस्थित हुये जिसमें पाया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बालाघाट के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 जो सेक द्वारा सुझााव दिये गये थे, उनका समावेश किया है। अभी संबंधित अधिसूचना के तालिका मे चाही गई जानकारी के अनुसार खनिज रेत हेतु लीजवार " माइनेबल मिनरल पोटेंशियल '' (घनमीटर में) (60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एंव चोड़ाई के साथ) उन्न्यन दिया गया है। अतएव उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त निम्न जानकारी को जिला सर्वेक्षण

रिपोर्ट में भी समाहित किया जाना प्रस्तावित हैः–

- ✓ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियॉ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बालाघाट जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है तथा पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी भी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।

- ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.मे) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी को भी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई कि वे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

**(ए.ए. मिश्रा)**
**सदस्य सचिव**

**(डॉ. पी.सी. दुबे)**
**अध्यक्ष**

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- 'B'**
**Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4$^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner's Name, Contact details etc.

g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

    **नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौघों की ऊॅचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊॅचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- 'C'**
**Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- 'D'**
**General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained